डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 62 ● अंक 2 ● भोपाल ● 16-30 जून, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

फसल निर्यात करने के लिये एपिडा की तर्ज पर बनेगा बोर्ड

जबलपुर में हुए राज्य-स्तरीय किसान महा-सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के किसानों की फसल निर्यात करने के लिये एपिडा (Agricultural and Processed Food Products Export Devlopment Authority) की तर्ज पर प्रदेश में बोर्ड का गठन किया जायेगा। श्री चौहान जबलपुर में कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत आयोजित राज्य-स्तरीय किसान महा-सम्मेलन में बड़ी संख्या में मौजूद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ग्रीष्मकालीन उड़द भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उन्होंने उड़द उत्पादक किसानों से आग्रह किया कि कृषक समृद्धि योजना में अपना पंजीयन करायें, ताकि उन्हें भी योजना का समय लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती का विकास और किसान का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खेतिहर परिवारों के बेटा-बेटी कृषि आधारित उद्योग-धंधे स्थापित करें। राज्य सरकार उन्हें 10 लाख से 2 करोड़ रूपये तक ऋण उपलब्ध करवाएगी। इस ऋण की गारंटी भी राज्य सरकार लेगी। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक हब और फुड चेन बनाई जायेगी। कच्चे माल के प्र-संस्करण की व्यवस्था की जायेगी। किसानों को कृषक समृद्धि योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के बच्चों की शिक्षा संस्थानों की फीस भी राज्य सरकार भरेगी। आवश्यकतानुसार किसान परिवार के सदस्यों का प्रायवेट अस्पताल में ईलाज कराने की पूरी व्यवस्था की जायेगी। किसानों को बिजली बिलों की परेशानी से राहत देने के लिये जुलाई माह में बड़े पैमाने पर शिविर लगाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि किसान परिवार के बच्चों को भी शिक्षा विभाग की लेपटॉप योजना का लाभ दिया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के बच्चे खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और नया मध्यप्रदेश गढ़ें।

राज्य-स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक जमाना था, जब प्रदेश के किसान बिजली, सिंचाई, बैंक के कर्ज और सड़क की बदहाली के कारण चैन से खेती नहीं कर पाते थे। उन्होंने कहा कि आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज प्रदेश में विद्युत उत्पादन 18 हजार 354 मेगावॉट तक पहुँच गया है। किसानों को भरपूर बिजली मुहैया कराई जा रही है। सिंचाई का रकबा 40 हजार हेक्टेयर हो गया है, किसानों के खेतों में पाईप लाईन से आवश्यकतानुसार भरपूर पानी पहुँचाया जा रहा है। किसान को अब बैंक ऋण पर भारी ब्याज नहीं देना पड़ता है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर बैंक से ऋण लेकर किसान खेती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल शहरों से जुड़ गये हैं। फसल बीमा योजना और सूखा राहत राशि की बड़े पैमाने पर व्यवस्था से किसान निश्चिंत होकर खेती को लाभ का धंधा बनाने में जुट गये हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 10 लाख 80 हजार 228 पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में रबी वर्ष 2018-19 में उपार्जित गेहूँ की 265 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कुल प्रोत्साहन राशि 2 हजार 245 करोड़ ऑनलाईन ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। खेती के क्षेत्र में नया इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश में खेती से होने वाली आमदनी किसानों के लिये समृद्धि का सशक्त माध्यम बने।

किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा 16 हजार करोड़ से अधिक ऋण

भोपाल। प्रदेश के किसानों को इस वर्ष सहकारी बैंकों से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 16 हजार करोड़ रुपये अधिक ऋण दिया जायेगा। इस लक्ष्य के अन्तर्गत पिछले माह के अंत तक 1700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर मुहैया करवाई जा चुकी है।

सहकारिता विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पावधि फसल ऋण योजना में पिछले वर्ष 12 हजार 797 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया था। वर्ष 2016-17 में किसानों को वितरित ऋण राशि वर्ष 2015 की तुलना में 760 करोड़ रुपये अधिक थी।

प्रदेश में 31 मार्च, 2018 की स्थिति में किसानों को 57 लाख 33 हजार किसान क्रेडिट कार्ड वितरित कर दिये गये हैं। इसमें से 3 लाख 70 हजार किसान क्रेडिट-कार्ड वर्ष 2017-18 में जारी किये गये हैं। सहकारी बैंक द्वारा किसानों को रूपे क्रेडिट-कार्ड जारी किये गये हैं।

सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को डीएमआर खातों के माध्यम से ऋण वितरण किया जा रहा है। प्रत्येक लेन-देन की जानकारी किसान को एसएमएस के माध्यम से मोबाइल फोन पर दी जा रही है।

फिशरमैन क्रेडिट योजना में 63 हजार कार्ड बने

भोपाल। प्रदेश में किसानों के समान ही मत्स्य पालकों को भी 2009-10 से फिशरमैन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। लगभग 63 हजार विभिन्न वर्ग मत्स्य पालक समिति के सदस्यों को इसका लाभ मिल चुका है। वर्ष 2018-19 में 10 हजार मत्स्य पालकों के क्रेडिट कार्ड बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मत्स्य पालन मंत्री श्री अन्तर सिंह आर्य ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि योजना की शुरूआत में मत्स्य पालकों को इनपुट्स के लिये 3 प्रतिशत ब्याज दर पर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाये गये थे। वर्ष 2011-12 में ब्याज दर घटाकर एक प्रतिशत और पुन: वर्ष 2012-13 में जीरो प्रतिशत कर दी गई है।

कृषि उपज मंडियों में 33 हजार से अधिक हम्माल-तुलावटियों को दी गई मदद

भोपाल। मध्यप्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में काम करने वाले 33 हजार 600 से अधिक हम्माल-तुलावटियों को विभिन्न योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है। अब तक इन्हें विभिन्न योजनाओं में करीब 10 करोड़ की मदद दी गई है। हम्माल-तुलावटियों के परिजनों को प्रसूति सहायता, विवाह के लिये सहायता, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना की स्थिति में मदद के साथ-साथ इनके बच्चों के लिये छात्रवृत्ति और मेधावी छात्र पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है।

संबल योजना की निगरानी समिति में होगी महिलाओं की भागीदारी-मुख्यमंत्री

32 हजार तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मिली 6 करोड़ 74 लाख बोनस राशि

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भलाई के लिये क्रियान्वित मुख्यमंत्री जन–कल्याण (संबल) योजना की पंचायत और वार्ड–स्तर पर सतत निगरानी की जायेगी। निगरानी का उद्देश्य होगा अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करना। उन्होंने कहा कि निगरानी समिति 5 सदस्यीय होगी और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी। श्री चौहान छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा नगर में तेन्दूपत्ता संग्राहक एवं असंगठित श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर घोषणा की कि सिंगोड़ी में सरकारी कॉलेज और अमरवाड़ा में आईटीआई खोली जायेगी। उन्होंने कहा कि शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या होने पर एमएससी पाठ्यक्रम की क्लासेस भी प्रारंभ करवाई जायेंगी। श्री चौहान ने नीट परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके साथ फोटो निकलवाई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हित–लाभ भी वितरित किये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में छिन्दवाड़ा जिले में लगभग 87 करोड़ लागत के 21 निर्माण कार्यों का भूमि–पूजन और लोकार्पण किया। करीब 32 हजार तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को 6 करोड़ 74 लाख रुपये बोनस राशि ऑनलाइन वितरित की। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में आये तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण–पादुकाएँ पहनाईं और पानी की कुप्पी भेंट की। महिला तेन्दूपत्ता संग्राहकों को साड़ियाँ भेंट की गईं। श्री चौहान ने सम्मेलन में गरीब, श्रमिक और किसान कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संबल योजना में श्रमिकों के साथ–साथ गरीब तबके के अन्य वर्गों और ढाई एकड़ तक की भूमि के स्वामित्व वाले किसानों को भी लाभान्वित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि संबल योजना इन वर्गों को समाज की मुख्य–धारा से जोड़ेगी। सम्मेलन में राष्ट्रीय अनुसूचित–जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उईके, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, महापौर श्रीमती कांता सदारंग, भारिया विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला भारती, विधायक सर्वश्री चौधरी चन्द्रभान सिंह, पं. रमेश दुबे, नानाभाऊ मोहोड़ और नत्थन शाह कवरेती, महाकौशल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री संतोष जैन, अन्य जन–प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में तेन्दूपत्ता संग्राहक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, किसान एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

प्रदेश में नहरों से सिंचाई में 433 प्रतिशत की वृद्धि

भोपाल। मध्यप्रदेश में नहरों से सिंचाई का प्रतिशत आज बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर हो चुका है। यह वर्ष 2003 में मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर था। जनसम्पर्क एवं जल–संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने बताया कि बीते 14 वर्षों में नहरों से सिंचाई कार्य में 433 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मंत्री डॉ. मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शनिवार, 23 जून को मध्यप्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से रू–ब–रू होंगे। प्रधानमंत्री इस दिन राजगढ़ जिले की मोहनपुरा सिंचाई योजना का लोकार्पण करेंगे। राजगढ़ जिले में मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई योजनाओं से लगभग आठ लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी। इन दोनों योजनाओं से बांध से लगे क्षेत्रों की पेयजल समस्या भी समाप्त हो जायेगी।

डॉ. मिश्र ने बताया कि प्रदेश में प्रति माह नवीन सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के समुचित पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा रही हैं। विभिन्न परियोजनाओं के लिये आवश्यकतानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ विस्थापितों को दिया जाता है, जिससे वे पूर्व की तुलना में नई बसाहट में अधिक सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। नई सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति के क्रम में इस माह मंत्रि–परिषद द्वारा डिण्डौरी और दमोह जिले की सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

'समाधान एक दिन' में 13 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण

भोपाल। "समाधान एक दिन" के तहत प्रदेश में अब तक 13 लाख 36 हजार आवेदनों का निराकरण किया गया है। गत जनवरी 2018 से शुरू की गई इस सेवा के तहत नागरिकों को 34 सेवायें एक दिन में दी जा रही हैं। यह जानकारी गत दिवस मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान दी गयी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले "समाधान एक दिन" के क्रियान्वयन में डिंडोरी, भिंड, होशंगाबाद, सागर और मंडला जिलों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस दौरान सी.एम. हेल्पलाईन में निराकरण की स्थिति का प्रस्तुतीकरण भी देखा। सी.एम. हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण में जिलों में होशंगाबाद, देवास, उज्जैन, नीमच और बैतूल, जिला पंचायतों में इंदौर, अलिराजपुर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और होशंगाबाद तथा नगर–निगमों में सिंगरोली, रतलाम, देवास, छिंदवाड़ा और भोपाल अग्रणी रहे।

इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी–कर्मचारियों में सर्वश्री अरविंद पटेरिया सहायक यंत्री सागर नगर निगम, रीतेश तिवारी आर.टी.ओ. रायसेन, गुलाबसिंह बघेल तहसीलदार भितरवार, अनित तंतुवाय सहायक आपूर्ति अधिकारी शहडोल, राजेन्द्र बर्मन निरीक्षक गृह होशंगाबाद, सुश्री हुमा हुजूर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रायसेन, अफजल अमानुल्लाह सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शहडोल और सुश्री शिवानी मिश्रा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी शामिल हैं।

ग्रीष्मकालीन मूँग खरीदने के लिये किसानों का किया जा रहा है पंजीयन

भोपाल। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूँग की मण्डी विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,575 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे होने पर किसानों से 12 जिलों के मूँग उपार्जन केन्द्रों पर 21 जून से खरीदी की जायेगी। किसानों के पंजीयन का कार्य 20 जून तक किया जायेगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूँग खरीदी के लिये 12 जिलों होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, हरदा, विदिशा, गुना, देवास, इंदौर, धार और बालाघाट में उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं।

मूँग के पंजीयन के समय उत्पादक किसानों को मूँग के रकबे के भू–अभिलेख, आधार–कार्ड, मोबाइल नम्बर और बैंक खाते के आईएफसी कोड की जानकारी देनी होगी। मूँग की खरीदी के लिये किसानों के पंजीयन का कार्य उन्हीं जिलों में किया जा रहा है, जहाँ मूँग की बोनी का रकबा 2000 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक है। पंजीकृत किसान के रकबे का सत्यापन पोर्टल पर किया जायेगा।

कृषि उपज मण्डियों में इलेक्ट्रॉनिक तौल–काँटे की सुविधा

प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में किसानों द्वारा बेची जाने वाली उपज का सही तौल हो सके, इसके लिये मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 257 कृषि उपज मण्डियों में इलेक्ट्रॉनिक तौल–काँटे की व्यवस्था की है। मण्डी समितियों में 130 इलेक्ट्रॉनिक तौल–काँटे 10 से 50 टन क्षमता के और 6439 इलेक्ट्रॉनिक तौल–काँटे एक क्विंटल से 5 क्विंटल क्षमता तक के लगाये गये हैं।

राज्य की समृद्धि और विकास का आधार हैं बैंक : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य–स्तरीय बैंकर्स समिति की 168वीं बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य–स्तरीय बैंकर्स समिति की 168 वीं बैठक में कहा है कि बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध रहे। स्व–रोजगार योजनाओं का ऋण वितरण पारदर्शिता के साथ किया जाये। सामाजिक सुरक्षा योजना के हितग्राहियों और मनरेगा के श्रमिकों को पेंशन और मजदूरी भुगतान की समुचित सुविधा उपलब्ध करवायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़े जिलों में जमा–ऋण–अनुपात को बढ़ाने और ग्रामीण अंचल में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जायें। बिजनेस प्रतिनिधि और चलित बैंकिंग की व्यवस्थाओं को विस्तारित किया जाये। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। बैठक में सर्व–समिति से निर्णय लिया गया कि आगामी 4 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार मेले आयोजित किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बैंकर्स की वर्ष 2018–19 की कार्य–योजना का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंक राज्य की समृद्धि और विकास का आधार हैं। कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले कार्य, बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीदी और प्रोत्साहन राशि के लगभग 25 हजार करोड़ रुपये बैंकों में जमा किये जा रहे हैं। किसानों एवं अन्य पात्र हितग्रहियों को उन्हें स्वीकृत राशि प्राप्त करने में असुविधा और विलंब नहीं हो। बैंक सुनिश्चित करें कि शाखाओं में नगदी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। मुख्यमंत्री ने बैंकर्स को स्व–रोजगार योजनाओं में लक्ष्य से 13 प्रतिशत अधिक उपलब्धि हासिल करने के लिये बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्व–रोजगार योजनाओं के ऋण वितरण के साथ ही स्व–रोजगार के अवसरों की सहज उपलब्धता का वातावरण भी बनाया जाये। इससे जनता में बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। श्री चौहान ने रोजगार मेलों में ऋण वितरण की व्यवस्था करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ ही स्व–सहायता समूहों और माइक्रो फाइनेंसिंग कम्पनियों को भी मेले में शामिल किया जाना चाहिए। मेले में राज्य और केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं के हितग्राहियों के लिये ऋण वितरण की व्यवस्था होना चाहिए।

श्री चौहान ने कहा कि बैंकर्स द्वारा ऐसा मॉडल तैयार किया जाये कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पेंशनर्स और मनरेगा के श्रमिकों को, उनके गांवों में ही आसानी से स्वीकृत राशि प्राप्त हो सके। उन्होंने बैंकर्स को कृषि क्षेत्र में स्व–रोजगार के अवसर सृजित करने, कृषक युवा उद्यमी योजना पर फोकस करने और अधिक से अधिक ऋण वितरण के लिये प्रेरित किया।

श्री चौहान ने राज्य में 9000 करोड़ रुपये का कैश फ्लो बनाये रखने, साख सीमा में वर्ष 2017–18 में 13 प्रतिशत और वर्ष 2018–19 में 14 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित करने और जमा–ऋण–अनुपात के लक्ष्य से 3.06 प्रतिशत अधिक की वृद्धि के लिये बैंकर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 40 प्रतिशत से कम जमा–ऋण–अनुपात वाले क्षेत्रों में बैंकर्स विशेष ध्यान दें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया सौर ऊर्जा चलित इलेक्ट्रिक कार का शुभारम्भ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां मंत्रालय में विश्व पर्यावरण दिवस पर सौर ऊर्जा से चलने वाली इलैक्ट्रिक कार का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राज्य में ई– वाहन के संचालन की शुरुआत हो गई है ।

यह इलैक्ट्रिक कार सौर ऊर्जा से चार्ज होगी। एक बार चार्ज होने पर 140 किलोमीटर तक चलेगी। प्रति किलोमीटर लागत मात्र अस्सी पैसे आएगी। प्रत्येक वाहन से हर साल साढ़े चार टन कार्बन डायआक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। ऐसे वाहन से पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि धरती का तापमान दिनों–दिन तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते वाहनों की संख्या से होने वाला प्रदूषण शहरों के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होने कहा कि सौर ऊर्जा चलित इलैक्ट्रिक वाहन, प्रदूषण रोकने की दिशा में एक कदम है। ऐसी पर्यावरण मित्र टेक्नालाजी का स्वागत है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वल्लभ भवन कैंटीन में पर्यावरण विभाग द्वारा स्थापित प्लास्टिक बोतल नष्ट करने की मशीन का भी शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि यह वर्ष प्लास्टिक मुक्त देश और प्रदेश बनाने के प्रयासों को समर्पित है।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनुपम राजन, नवकरणीय ऊर्जा विभाग और ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

126 लघु सिंचाई योजनाओं से 54 हजार हेक्टेयर में होगी सिंचाई

भोपाल। प्रदेश में गत वर्ष 126 लघु सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं से लगभग 54 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई है। सिंचाई में ''पर ड्रॉप–मोर क्रॉप'' के सिद्धांत पर अमल किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में वाटर कोर्स और फील्ड चैनल बनवाये जा रहे हैं। स्वीकृत 23 परियोजनाओं में से वैनगंगा, बाघ और कुंवरचैन सागर परियोजनाओं और कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई नालियों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। साथ ही, डेढ़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विकास कार्य भी करवाये जा चुके हैं।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए.
स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039
फोन.–0755 2725518, 2726160 फेक्स–0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

उद्यमिता, रोजगार निर्माण, स्मार्ट गांव, नदियों का संवर्धन, स्वास्थ्य शिक्षा पर होगा फोकस

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने साझा किया विकास का विज़न

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के विकास की दृष्टि और सोच साझा करते हुये कहा है कि अगले पांच वर्षों में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने, पर्यावरण संवर्धन, नदियों का संवर्धन, स्मार्ट गाँव बनाने और उद्यमिता के क्षेत्र में रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने पर ध्यान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री यहाँ एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

श्री चौहान ने कहा कि पिछले पन्द्रह वर्षों में मध्यप्रदेश ने विकास के नये कीर्तिमान रचे हैं। ऊर्जा की उपलब्धता 18 हजार मेगावॉट हो गई है। पहले लोग अंधेरे का सामना करते थे। आज चौबीसों घंटे ऊर्जा की उपलब्धता है। किसानों को भरपूर पानी मिल रहा है। आज 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की उद्योग नीति के प्रावधानों से आकर्षित होकर प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की इसमें बड़ी भूमिका रही है। पिछले दो सालों में दो लाख करोड़ रूपये का निवेश आया है। विशेष रूप से आईटी, दवा उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश आ रहा है। उन्होंने बताया कि नई वेयर हाऊसिंग नीति बनाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमुदाय के सवालों के जवाब दिये। उन्होंने कहा कि जल्दी ही शिक्षकों, पुलिस कर्मियों की भर्ती की जायेगी। निजी स्कूलों में ज्यादा फीस वसूली पर नियंत्रण के लिये व्यवस्था बनाई जायेगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये भी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सायबर अपराधों के नियंत्रण के लिये जल्दी ही सायबर कानून के पालन की स्थिति की समीक्षा की जायेगी और सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों से चर्चा की जायेगी ताकि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हो।

श्री चौहान ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में निजी क्षेत्र का एकाधिकार नहीं होना चाहिये। सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्थाओं को और ज्यादा चुस्त–दुरूस्त बनाया जायेगा। शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा करते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयोग के तौर पर बैतूल में एक सर्वसुविधायुक्त स्कूल की स्थापना की जा रही है। इस स्कूल में आसपास के गाँवों के बच्चों को लाकर पढ़ाया जायेगा। उनके आने–जाने के लिये परिवहन की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रयोग सफल होने पर इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा और लोक सभा के चुनाव एक साथ होना चाहिये। चुनाव के लिये राज्य की ओर से फंडिंग होना चाहिये। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होने से दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाने में बाधाएं आती हैं और राज्य का विकास रूक जाता है। साथ ही पूरी ऊर्जा चुनाव कराने में लग जाती है जिसमें समय और संसाधन दोनों का अपव्यय होता है।

सौभाग्य योजना से 15 लाख 74 हजार से अधिक घरों में पहुंची बिजली

14 जिलों में हुआ शत–प्रतिशत विद्युतीकरण

भोपाल। मध्यप्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य में अब तक 15 लाख 74 हजार 689 घरों को बिजली कनेक्शन देकर रौशन किया जा चुका है। योजना में शेष घरों को अगामी अक्टूबर माह तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार की समन्वित पहल पर ऐसे सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो वर्षों से रोशनी से वंचित थे। थी। इसके लिए सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य योजना" के बेहतर परिणाम सामने आये हैं। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा इस दिशा में समुचित प्रयास कर ऐसे सभी अंधेरे में डूबे घरों को बिजली कनेक्शन सहजता और सरलता से उपलब्ध कराकर उनके घर रोशन किए जा रहे हैं।

राज्य के 14 जिलों इंदौर, मंदसौर, नीमच, आगर–मालवा, देवास, खण्डवा, उज्जैन, अशोकनगर, हरदा, रतलाम, शाजापुर, भोपाल, सीहोर एवं धार में शत–प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर घरों को रोशन कर दिया गया हैं। सौभाग्य योजना में अगले कुछ दिनों में 5 अन्य जिलों में शत–प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूर्ण किया जा रहा है। ये जिले हैं होशंगाबाद (98 प्रतिशत), झाबुआ (97 प्रतिशत), ग्वालियर (96 प्रतिशत), दतिया (94 प्रतिशत) एवं अलीराजपुर (94 प्रतिशत)। ये जिले तेजी से आगे चल रहे हैं।

योजना के क्रियान्वयन में तीनों विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रीय एवं स्थानीय अभियंता और कार्मिक पूरी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, ताकि योजना का लाभ हर बिजली विहीन परिवार के घर तक पहुँच सके। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को क्षेत्र के 20 जिलों के कनेक्शन विहीन घरों को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। कंपनी ने अब तक 5 लाख 07 हजार 739 घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने क्षेत्र के बिजली कनेक्शन विहीन घरों के विद्युतीकरण के दिये गये लक्ष्य के विरूद्ध 6 लाख 29 हजार 419 घरों को रोशन किया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली कनेक्शन विहीन घरों को बिजली सुविधा मुहैया करवाने के दिये गये लक्ष्य के विरुद्ध 3 लाख 70 हजार 187 घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए हैं।

रोजगार मेलों में 2581 बेरोजगारों को मिला रोजगार

भोपाल। राजगढ़ जिला मुख्यालय में रोजगार मेला, देवास में टेक्सटाइल जॉब फेयर और सिंगरौली में टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी जॉब फेयर लगाये गये। इन मेलों में 5 हजार 347 बेरोजगार युवाओं ने पंजीयन करवाया। इन बेरोजगारों में से 2521 को विभिन्न कम्पनियों द्वारा लेटर ऑफ इंटेन्ट जारी किये गये।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजगढ़ में 3489 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इनमें से 1538 को लेटर ऑफ इंटेन्ट दिये गये। देवास में 845 रजिस्ट्रेशन हुए और 246 को लेटर ऑफ इंटेन्ट दिये गये तथा सिंगरौली में 1013 रजिस्ट्रेशन हुए एवं इनमें से 797 को लेटर ऑफ इंटेन्ट जारी किये गये।

पटवारी के लिये चयनित अभ्यार्थियों की काउंसलिंग 23 जून को

भोपाल। पटवारी भर्ती परीक्षा–2017 के माध्यम से चयनित अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं काउंसलिंग 23 जून को होगी। पूर्व में यह काउंसलिंग 26 मई को होनी थी, जो कि उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण निरस्त कर दी गयी थी।

लहसुन–प्याज संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश जारी

भोपाल। राज्य शासन ने लहसुन–प्याज भावांतर योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये हैं। किसानों द्वारा क्रेता व्यापारी को बेचे गये लहसुन/प्याज के विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत या 10 हजार रूपये जो भी कम हो का क्रेता व्यापारी द्वारा किसान के बैंक खाते में आरटीजीएस अथवा एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश 5 जून से अधिसूचित मंडियों में लागू होंगे।

संबल योजना कमजोर वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगी

मुख्यमंत्री द्वारा मंडला में वन्या प्लस डबल फोर्टीफाईड नमक वितरण योजना का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संबल योजना समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ेगी। इस योजना से इन वर्गों के जीवन में खुशहाली आयेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर संबल योजना में पंजीकृत हितग्राहियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के हित–लाभ वितरित किये जायेगे। श्री चौहान मंडला जिले के ग्राम अंजनिया में तेन्दूपत्ता संग्राहक और असंगठित श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबल योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अगले चार साल में प्रदेश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति के पास खुद का घर होगा। राज्य सरकार इन चार वर्षों में लगातार हर वर्ष 10–10 हजार पक्के मकान बनाकर आवासहीन गरीब और कमजोर वर्गों को सुलभ करवाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में राज्य स्तरीय आयरन और आयोडीनयुक्त वन्या प्लस डबल फोर्टीफाईड नमक वितरण योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया और योजना की प्रचार सामग्री का विमोचन किया। श्री चौहान ने बताया कि इस योजना से प्रदेश के 20 जिलों के 89 आदिवासी बाहुल्य विकासखंड के हितग्राही लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने महिला तेन्दूपत्ता संग्राहकों को पहनाई चरण–पादुकाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में महिला तेन्दूपत्ता संग्राहक सेवंती बाई, गलियारी बाई, सत्यवती बाई और लमिया बाई को अपने हाथों से चरण–पादुका पहनाई, साड़ी और पानी की कुप्पी भेंट की। इस अवसर पर मंडला और डिण्डोरी जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को कुल 25 करोड़ रुपये की बोनस राशि भी वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने असंगठित श्रमिक सुदर्शन, श्री राम और लमिया बाई को संबल योजना के स्मार्ट कार्ड भी प्रदान किये।

श्री चौहान ने जे.ई.ई परीक्षा में सफल हुए मंडला एवं डिण्डोरी जिले के विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ दीं और उनके साथ फोटो निकलवाई। श्री चौहान ने इस मौके पर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हित–लाभ में वितरित किये।

सम्मेलन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे, सासंद श्री फग्गन सिह कुलस्ते और श्रीमती सम्पतिया उईके, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉ. शिवराज शाह, म.प्र.लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी, स्थानीय विधायक, अन्य जन–प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक, तेन्दूपत्ता संग्राहक तथा ग्रामीणजन उपस्थित थे।

राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से जुड़ीं मध्यप्रदेश की 58 कृषि उपज मंडियां

अभिनव पहल

- **प्रदेश की 58 कृषि उपज मण्डियाँ राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ीं।**
- **13 कपास मण्डियों को भी राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा रहा है।**
- **ई–नाम पोर्टल पर 49 लाख क्विंटल कृषि जिन्सों का हुआ व्यापार।**

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) एक पैन–इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। यह कृषि उपजों के लिये एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने का सशक्त माध्यम है। कृषि उपज मण्डी से संबंधित सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिये यह ई–नाम पोर्टल सिंगल विण्डो सेवा प्रदान कर रहा है। इस पोर्टल में उपज के आगमन और कीमतों तथा उपज को खरीदने और बेचने के व्यापारिक प्रस्तावों के प्रावधान को शामिल किया गया है। प्रदेश में ई–नाम पोर्टल के माध्यम से अभी तक 58 कृषि उपज मण्डियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा चुका है।

प्रदेश में ई–नाम पोर्टल की शुरूआत भोपाल की पण्डित लक्ष्मीनारायण शर्मा कृषि उपज मण्डी करोंद से की गई। योजना के पहले चरण में प्रदेश की 19 चयनित कृषि उपज मण्डियों को इस पोर्टल से जोड़ा गया। ई–नाम पोर्टल से जुड़ी कृषि उपज मण्डियों में 6 जिन्सों पर ऑनलाईन ट्रेडिंग की जा रही है। योजना के दूसरे चरण में 30 और तीसरे चरण में 8 कृषि उपज मण्डियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना में शामिल किया गया है। अब तक प्रदेश की 58 कृषि उपज मण्डियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से जोड़ा जा चुका है।

इसके साथ ही, 13 कपास मण्डियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से जोड़ने का कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना में अब तक करीब 12 लाख किसानों से 19 हजार लायसेंस धारी व्यापारियों ने ई–प्लेटफार्म के माध्यम से करीब 49 लाख क्विंटल कृषि जिन्सों का व्यापार किया है। प्रदेश में ई–नाम पोर्टल की सभी 58 मण्डियों में कृषि उपज के गुणवत्ता परीक्षण के लिये वृहद एसेइंग एण्ड ग्रेडिंग लैब स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। ई–नाम पोर्टल में देश के 18 राज्यों में मध्यप्रदेश की स्थिति गेट एन्ट्री और एसेइंग में प्रथम तथा बिड क्रिएशन और सेल ऐग्रीमेंट में तृतीय रही है। ज्ञातव्य हैकि देश में अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की शुरूआत की थी। इसका मकसद किसानों को उनकी उपज का राष्ट्रीय स्तर पर सही दाम दिलवाना है।

कृषि उपज मंडियों में किसानों के लिये है रियायती दर पर भोजन थाली की सुविधा

भोपाल। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में फसल बेचने आने वाले किसानों को 5 रुपये की न्यूनतम दर पर भोजन थाली उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा इसके लिये मंडियों को अनुदान राशि जारी की गई है। किसानों की सुविधा के लिए कृषि उपज मंडियों में किसान विश्राम भवन भी बनवाये गये हैं। मंडी परिसरों में वॉटर कूलर जैसे बुनियादी सुविधायें भी उपलब्ध करवाई गई हैं।

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना

राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना लागू की गई है। इस योजना में किसान की कृषि कार्य करते हुए मृत्यु होने। अपंगता होने पर प्रभावित किसान को मंडी निधि से अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। अब तक 3 हजार 332 प्रभावित किसानों को 30 करोड़ रुपये की राशि अनुदान स्वरूप उपलब्ध करवाई गई है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला में 36 लाख 20 हजार से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन

भोपाल। महिलाओं और बच्चों को घातक धुँआ से मुक्ति दिलाने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने कमजोर वर्ग को नि:शुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में प्रदेश में रिकार्ड 36 लाख 20 हजार 164 कनेक्शन वितरित कर घरों में इन्स्टॉल करवा दिये गये हैं। खाद्य आयुक्त श्रीमन शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में प्रदेश के एस.ई.सी.सी. सूची में शामिल 72 लाख 38 हजार 900 परिवारों में से 46 लाख 86 हजार 547 परिवारों के के.वाय.सी. भरे जा चुके है। के.वाय.सी. भरे हुए आवेदनों में से 38 लाख 76 हजार 77 परिवारों के आवेदन योजना अन्तर्गत स्वीकृत किये जा चुके है। स्वीकृत आवेदनों में से 36 लाख 20 164 परिवारों में नि:शुल्क गैस कनेक्शन वितरित कर स्थापित किये जा चुके है। खाद्य आयुक्त श्री शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन वितरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में 1197 डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा मई माह में 4 लाख 11 हजार 73 के.वाय.सी. भरे गये और 2लाख 43 हजार 522 परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित किये गये।

गरीब और मेहनतकश लोगों की खुशहाली ही राज्य सरकार का लक्ष्य : मुख्यमंत्री

रायसेन में तेन्दूपत्ता संग्राहक एवं असंगठित श्रमिक सम्मेलन सम्पन्न

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के गरीब और मेहनतकश लोगों के जीवन को खुशहाल बनाना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन–कल्याण (संबल) योजना गरीबों और मेहनतकश लोगों के विकास के लिये बनाई है। इस योजना में पात्र पंजीकृत हितग्राहियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। श्री चौहान रायसेन में तेन्दूपत्ता संग्राहक एवं असंगठित श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना में पंजीकृत श्रमिकों को आगामी 13 जून को विकासखंड मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित कर हित–लाभ वितरित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोयेगा। हर गरीब व्यक्ति को आवासीय जमीन का पट्टा देकर पक्के मकान का मालिक बनाया जायेगा। हर गरीब परिवार के लिये मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी। गरीब परिवार के बच्चों की पूरी पढ़ाई की फीस राज्य सरकार भरेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में घोषणा की कि रायसेन जिला मुख्यालय पर सर्व–सुविधायुक्त इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जायेगा। इससे जिले के प्रतिभाशाली बच्चों को इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिये अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं।

श्री चौहान ने इस अवसर पर रायसेन जिले में 172 करोड़ लागत के विकास एवं निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के 821 हितग्राहियों को 53 लाख 60 हजार रुपये सहायता राशि वितरित की। श्री चौहान ने अन्य योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को भी हित–लाभ वितरित किये और तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण–पादुका पहनाई तथा पानी की कुप्पी भेंट की।

सम्मेलन में वन मंत्री डॉ गौरीशंकर शेजवार, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा, खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, विधायक श्री रामकिशन पटेल, लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी, अन्य जन–प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान, श्रमिक तथा ग्रामीण उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में बेहतर है केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने बतायी केन्द्र की चार वर्ष की उपलब्धियाँ

भोपाल। जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने समाचार–पत्र प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान केन्द्र सरकार के सफल चार वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी दी। डॉ. मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विकास की नई ऊँचाईयँ छू रहा है। आज विश्व के लोकप्रिय नेताओं में श्री मोदी का सम्मनाजनक स्थान है। उज्जवला योजना, आवास योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के बहुआयामी लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही केन्द्र सरकार नए भारत के निर्माण के लिए समर्पित है।

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि गरीबों और जरूरतमतंदों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार ने प्रभावशाली ढंग से योजनाओं को लागू किया है। केन्द्र सरकार जनभावनाओं की हर कसौटी पर खरी उतरी है। पिछले चार वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा आम नागरिक का विश्वास अर्जित करने का ईमानदार प्रयास किया गया है। जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि आज देश में जरूरतमंदों को सभी आवश्यक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में भी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सफलता मिली है। वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति को घर उपलब्ध करवाने की दिशा में कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की एक–एक बूंद के सदुपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2014–18 की अवधि में 26.87 लाख हेक्टेयर भूमि में लघु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में कामयाबी मिली है। इसी तरह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा किसानों तक पहुँचाई गई है। ब्याज अनुदान कार्यक्रम के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए तीन लाख रूपये तक लोन कम वार्षिक ब्याज दर पर मुहैया करवाने का प्रावधान क्रांतिकारी है।

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने बताया कि जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार गतिशील है। मध्यप्रदेश सरकार भी इसी भावना से विकास के नये आयाम स्थापित कर रही है। डॉ. मिश्र ने केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रकाशित विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों के प्रकाशित ब्रोशर भी मीडिया प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाये।

कृषि विपणन पुरस्कार

कृषि उपज मंडियों में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि विपणन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। पिछले 4 वर्षों में लकी ड्रा से विजेता एक हजार 713 किसानों को करीब 5 करोड़ रुपये के पुरस्कार वितरित किये गये हैं। हर वर्ष प्रत्येक कृषि उपज मंडी में दो बार नर्मदा जयंती और बलराम जयंती पर ड्रा निकाले जा रहे हैं। 'क' श्रेणी की मंडी में विजेता किसान को 35 हार्स पॉवर का ट्रैक्टर इनाम स्वरूप दिया गया है। इसके अलावा किसानों को कृषि यंत्र और नगद राशि भी पुरस्कार स्वरूप दी गई है।

फ्लैट बिल योजना में हितग्राही भरेंगे वास्तविक बिजली बिल

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फ्लैट बिजली बिल योजना के हितग्राहियों का सरल और सुविधापूर्ण तरीके से व्यापक स्तर पर पंजीयन किया जाये। विद्युत वितरण केन्द्रों के साथ ही बड़े हाट और बाजार आदि सार्वजनिक स्थलों में शिविर लगाकर पंजीयन करवाया जाये। श्री चौहान मंत्रालय में ऊर्जा विभाग की घरेलू बिल सरल समाधान और सरल बिजली बिल योजनाओं के प्रस्तावित प्रारूप की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फ्लैट रेट योजना में पंजीकृत श्रमिकों को वास्तविक मासिक बिल का भुगतान करना हो, जो अधिकतम 200 रूपये तक होगा। यदि किसी का मासिक बिजली बिल 150 रूपये आता है, तो उसे बिल की वास्तविक राशि 150 रूपये ही जमा करनी होगी। इस व्यवस्था का व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दिये।

राजगढ़ जिले की मोहनपुरा सिंचाई योजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा तेन्दूपत्ता श्रमिकों को 23.21 लाख बोनस राशि वितरित

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 जून को राजगढ़ जिले की मोहनपुरा सिंचाई योजना का लोकार्पण करेंगे। श्री चौहान ने राजगढ़ जिला मुख्यालय में हुए अन्त्योदय सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई योजनाओं से राजगढ़ जिले में लगभग आठ लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से बांध से लगे क्षेत्रों की पेयजल समस्या भी समाप्त हो जायेगी।

श्री चौहान ने कहा कि 13 जून को प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। सम्मेलन में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरित किये जायेंगे। योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने ने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति इस योजना में शामिल होने के लिये सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। ढाई एकड़ तक के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि संबल योजना में पात्र हितग्राहियों को आवासीय जमीन के पट्टे दिये जायेंगे। साथ ही उन्हें मकान बनाने के लिये सरकार राशि भी उपलब्ध करवाएगी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब साढ़े 37 लाख गरीब परिवार ऐसे हैं, जिनके पास रहने के लिये अच्छे घर नहीं हैं। ऐसे सभी परिवारों को चरणबद्व तरीके से आवास निर्माण के लिये आगामी चार साल में राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में राजगढ़ जिले के 4436 तेन्दूपत्ता संग्राहकों की 23 लाख 21 हजार रुपये बोनस राशि उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। उन्होंने तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका पहनाई और पानी की कुप्पी भेंट की। श्री चौहान ने 175 स्व–सहायता समूहों को रोजगार शुरू करने के लिये तीन करोड़ के बैंक ऋण वितरित किये। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राजगढ़ जिले में 171.09 करोड़ के 12 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि–पूजन किया। इस अवसर पर सांसद श्री रोडमल नागर, विधायक सर्वश्री अमरसिंह यादव, हजारीलाल दांगी और कुवंर कोठार, अन्य जन–प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक, तेन्दूपत्ता संग्राहक और ग्रामीण उपस्थित थे।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने 90 लाख से अधिक किसानों को हेल्थ कार्ड वितरित

केन्द्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड किये जा रहे हैं मिट्टी परीक्षण के परिणाम

भोपाल। प्रदेश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वाइल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम में 90 लाख से अधिक किसानों को स्वाइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जा चुका है। प्रदेश में वर्ष 2015–16 से स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरण कार्य शुरू किया गया है। कृषि विभाग का मैदानी अमला स्वाइल हेल्थ कार्ड के आधार पर किसानों को उपयुक्त फर्टीलाइजर का उपयोग करने की समझाइश दे रहा है।

स्वाइल हैल्थ कार्ड कार्यक्रम में प्रदेश में 88.72 लाख कृषि जोतों से 23 लाख 19 हजार ग्रिड आधारित मिट्टी के नमूने लेकर उनका मिट्टी परीक्षण करवा कर फसलवार मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और उर्वरकों की आवश्यकता का विशलेषण किया गया है। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग की 50 मिट्टी परीक्षण शालाओं में मिट्टी का नमूना परीक्षण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्र और कृषि विश्वविद्यालय में संचालित 28 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में भी मिट्टी नमूना परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड से कृषि विभाग को हस्तानांतरित 26 प्रयोगशालाओं का तकनीकी दृष्टि से सुदृढीकरण किया गया है।

प्रयोगशालाओं में मिट्टी के सूक्ष्म तत्वों की जाँच की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के 313 विकासखण्डों में मिट्टी नमूना परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य शासन ने 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ मंजूर की हैं। प्रयोगशालाओं के भवनों के निर्माण का कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए खेतों की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए मिनी लैब के माध्यम से मिट्टी के नमूने का तत्काल परीक्षण करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। किसानों की जोतों से इकट्ठे किये गये मिट्टी के नमूनों के विश्लेषित परिणामों को केन्द्र सरकार के स्वाइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पर अपलोड भी करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने किया श्रमदान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में पशुपतिनाथमंदिर के समीप शिवना नदी के तट पर पहुँचकर आमजनों के साथ नदी संरक्षण के लिये श्रमदान किया। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से तगाड़ी में मिट्टी भरी और उसे उठाकर ट्रेक्टर ट्रॉली में डाला। मुख्यमंत्री का समर्पण देखकर अन्य जन–प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय निवासियों ने भी नदी के संरक्षण के लिये श्रमदान किया। यह अभियान जन–अभियान परिषद द्वारा संचालित है।

रंग लाने लगी हैं कोशिशें मातृ मृत्यु दर 48 अँक घटी

भोपाल। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को कम करने के प्रयास अब सार्थक परिणाम देने लगे हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वर्ष 2014 से 2016 तक के विशेष बुलेटिन में मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु में 48 अंकों की अभूतपूर्व गिरावट दर्ज हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक श्री एस. विश्वनाथन ने बताया है कि प्रदेश में वर्ष 2011–13 में मातृ मृत्यु दर 221 थी, जो अब घटकर मात्र 173 रह गई है। प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में 22 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

श्री विश्वनाथन ने कहा कि संस्थागत प्रसव, ए.एन.एम., आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, दस्तक अभियान आदि निरंतर जारी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के परिणाम अब आने लगे हैं। आने वाले वर्षों में यह गिरावट और अधिक स्पष्ट होगी। स्वास्थ्य संस्था स्तर से लेकर समुदाय स्तर तक प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया गया है कि गर्भ का पता चलते ही शीघ्र स्वास्थ्य केन्द्र में गर्भधात्री महिला का पंजीयन करवायें। इससे प्रसव पूर्व आवश्यक जाँचें, टीकाकरण, खून की कमी आदि का उपचार होने के साथ ही अन्य जटिलताओं पर काबू पाने में आसानी हुई है।

मिशन संचालक ने बताया कि उच्च जोखिम प्रसव की संभावनाओं वाली महिलाओं का नियमित फॉलोअप करके उनका सुरक्षित प्रसव कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में खून की कमी वाली गर्भवती महिलाओं को आयरन टेबलेट्स और अत्यधिक खून की कमी होने पर आयरन के इंजेक्शन दिये जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को खून भी चढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का नियमित पर्यवेक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थाओं में नर्सिंग सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से नर्सिंग मेंटर्स की तैनाती की गई है।

आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक केन्द्र बनाया जायेगा

मुख्यमंत्री ने ग्राम जाखावाड़ी में आदिवासियों के विकास के लिये किया विचार–विमर्श

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के बिछुआ विकासखंड के ग्राम जाखावाड़ी में आदिवासियों के विकास के लिये आदिवासी मुखियाओं से विचार–विमर्श किया तथा उनके विचारों से अवगत हुये। इस दौरान जिले के लगभग 250 सरपंच, जनप्रतिनिधि और अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने विकास के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किये। सभी ने अपने–अपने क्षेत्र में विकास के लिये चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह एक अलग तरह का कार्यक्रम है जिसमें लोगों की बात सुनने की कोशिश की गई और उनकी समस्याओं के निराकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान किया जायेगा। इसके लिये छोटे–छोटे तालाब व जल संरचनाओं का निर्माण किया जायेगा। माचागोरा बांध में पानी की उपलब्धता का परीक्षण कराया जायेगा और उसके आधार पर इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्ययोजना बनाई जायेगी। श्री चौहान ने श्रमिक कल्याण योजना से लाभान्वित करेंगे। उन्होंने श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबंधित अधिकारीगण घास की जमीन व वन भूमि के मामलों का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार आदिवासी सामुदायिक भवन बनाया जायेगा तथा एक ऐसा सांस्कृतिक केन्द्र बनाया जायेगा जहां आदिवासी संस्कृति का संरक्षण हो सके। उन्होंने गोंडी भाषा व संस्कृति के संरक्षण की योजना बनाने के लिये भी कहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला स्व–सहायता समूह का सम्मेलन करें और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की ओर ले जाये। श्री चौहान ने रोजगार मेला लगाने के निर्देश भी दिये जिसमें युवा स्व–रोजगार योजनाओं से लोग लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वनोपज आधारित कुटीर उद्योग की कार्ययोजना के संबंध में चर्चा कर नशामुक्ति की दिशा में एक अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के छूटे हितग्राहियों को आगामी 4 सालों में लगभग 40 लाख आवास उपलब्ध कराये जायेंगे।

इस अवसर पर प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास और जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, भारिया विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला भारती, विधायकगण सर्वश्री चौधरी चन्द्रभान सिंह, पं. रमेश दुबे, नत्थन शाह कवरेती और नानाभाऊ मोहोड, नगर पंचायत पिपलानारायणवार के अध्यक्ष श्री राजू परमार, संभागीय कमिश्नर श्री आशुतोष अवस्थी, आई.जी., डी.आई.जी., कलेक्टर श्री वेद प्रकाश, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी, पत्रकार तथा बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के सरपंच, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण जन उपस्थित थे।

प्रदेश में किसानों की आय दो गुना करने के लिए किये जा रहे हैं ठोस प्रयास

मंत्री–गणों की उपस्थिति में जिला मुख्यालयों पर हुए कृषक सम्मेलन

भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों की आय दो गुना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए रोड मेप के अनुसार ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये पिछले दो वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए उनके बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि जमा करवायी गई है।

दमोह– वित्तमंत्री श्री जयंत मलैया की उपस्थिति में किसान सम्मेलन हुआ कृषक समृद्धि योजना में 20 हजार 693 किसानों को 265 रुपये प्रति क्विंटल के मान से 34 करोड़ 72 लाख की प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खाते में जमा की गई। वित्तमंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा कि किसानों के हित में लिए गये निर्णय को पूरा करने के लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उदबोधन को सम्मेलन में उपस्थित किसानों ने टी.वी के माध्यम से सुना। कार्यक्रम में विधायक श्री लखन पटेल, विधायक उमादेवी खटीक भी मौजूद थी।

छिन्दवाड़ा– किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री गौरी शंकर विसेन की उपस्थिति में किसान सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता विधायक श्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने की। किसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि छिन्वाड़ा जिला कृषि के मामले में प्रगति जिले के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया कि जिले में 39 हजार 429 किसानों के बैंक खाते में करीब 76 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई गई है। उन्होंने कहा कि अब किसान एमपी एग्रो से कृषि यंत्र खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। खुले बाजार में अपनी पसंद का कृषि यंत्र ले सकते है। उन्हें पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा।

रीवा– मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र की उपस्थिति में किसान सम्मेलन हुआ। जिले में किसानों के बैंक खाते में 36 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जमा करवायी गई है। कार्यक्रम को सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने भी संबोधित किया। उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि पिछले डेढ़ दशक में बिजली, सड़क के मामले में उल्लेखनीय काम हुआ है।

रायसेन– वन मंत्री श्री गौरी शंकर शेजवार की उपस्थिति में किसान सम्मेलन हुआ। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में जिले के 42 हजार किसानों के खाते में करीब 116 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। श्री शेजवार ने कहा कि किसानों को उनकी माँग के अनुसार बिजली दी जा रही है। प्रदेश में किसानों को जीरो प्रतिशत दर पर कृषि ऋण दिया जा रहा है। सम्मेलन मे विधायक श्री रामकिशन पटेल भी मौजूद थे।

गुना– उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया की उपस्थिति में गवरमेन्ट कॉलेज परिसर में किसान सम्मेलन हुआ। आज जिले के 13 हजार 513 किसानों के खाते में उपार्जित गेहूँ 9 लाख 78 हजार 939 क्विंटल गेहूँ के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 25 करोड़ 78 लाख रुपये की राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। किसानों को संगोष्ठी में जैविक खेती, प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं अन्य कृषि और उद्यानिकी से संबंधित जानकारी दी गई।

उज्जैन– मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन की उपस्थिति में किसान सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में सांसद प्रो. चिन्तामणि भी मौजूद थे। जिले में 48 हजार 656 किसानों के खाते में 103 करोड़ 23 लाख रु. की राशि जमा कराई गई। सम्मेलन में उपस्थित किसानों ने एलईडी टी.वी के माध्यम से मुख्यमंत्री के उद्बोधन को सुना।

देवास– पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा की उपस्थिति में किसान सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में सांसद श्री मनोहर ऊंटवाल, विधायक खातेगांव श्री आशीष शर्मा मौजूद थे। जिले में 23 हजार 186 किसानों के बैंक खाते में 40 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि गेहूँ उपार्जन के बदले में जमा करवाई गई।

नरसिंहपुर– मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में कुटीर एवं ग्रामोउद्योग राज्य मंत्री श्री जालम सिंह पटेल की उपस्थिति में सम्मेलन हुआ। जिले के 19 हजार 54 किसानों के बैंक खातों में 34 करोड़ 11 लाख रुपये की राशि जमा करवाई गई। सम्मेलन में विधायक श्री गोविंद सिंह पटेल श्री संजय शर्मा भी मौजूद थे।

खरगौन– किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री बालकृष्ण पाटीदार की उपस्थिति में मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना में किसान सम्मेलन हुआ। किसानों ने मुख्यमंत्री के जबलपुर से दिये गये भाषण को एलईडी टी.वी के माध्यम से सुना। जिले के 26352 किसानों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि 39 करोड़ रुपये जमा करवाई गई।

विदिशा– उद्यानिकी राज्य मंत्री श्री सूर्य प्रकाश मीणा की उपस्थिति में आज किसान सम्मेलन हुआ। जिले के 38 हजार 739 किसानों के बैंक खातों में करीब 98 करोड़ रुपये की राशि सीधे पहुँची। श्री मीणा ने बताया कि प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उद्यानिकी फसल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कटनी– सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री संजय पाठक की उपस्थिति में कटनी में किसान सम्मेलन हुआ।जिले में 20 हजार 765 किसानों के बैंक खातों में 265 रुपये प्रति क्विंटल के मान से करीब 41 करोड़ रुपये की राशि सीधे जमा करवाई गई।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।